

21190

## असाधार्ण EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकारिक्त PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 518}

नई बिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1989/आवर्ण 28, 1911

No. 518] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1989/SRAVANA 28, 1911

इ.स. भाग में जिम्म पृथ्ठ संख्या की वासी है जिससे कि यह अलग संकालन के रूप में रेखा का सके

Separate Paging in given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रासम

(ग्राधिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

ग्रधिस् वेनाएं

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1989

का थ्रा. 652 (य्र) — केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन प्रधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रवत्त मिन्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के प्रधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए भावेदन पर विचार करने के पश्चात बैंक ग्रांफ यंजावुर लिमिटेड की बाबत 19 ग्रगस्त, 1989 को कारबार की समाप्ति से तारीख 19 विसम्बर, 1989 तक जिसके अंतर्गन यह तारीख मी है, की कालावधि के लिए प्रधिस्थान ब्रादेण करती है और प्रधिस्थान की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध

सभी कार्रवाहियों और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या वालू रखने को इस गर्त के प्रधीन रहते हुए स्थिगत करती है कि ऐसे स्थान से उक्त प्रधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (ख) के प्रधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी गिक्तयों के प्रयोग पर या उक्त प्रधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी गिक्तयों के प्रयोग पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- 2. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि वैंक प्रांफ यंजावूर लिमिटेड को मंजूर की गयी अधिस्थगत की काला-विधि के दौरान, वह वैंक भारतीय रिजर्व की लिखित अनुत्री के बिना;
  - (क) प्रपने दाधित्कों और बाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यया कोई उधार या प्रप्रिम नहीं देगा, कोई दासित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके

पक्ष्वात उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझीता या ठहराव नहीं करेगाः

- (1) प्रत्येक बचत या चालू खाते में या किसी प्रान्य निक्षेप में चाहें वह किसी भी नाम जात हो, कुल प्रतिशेष के 50 प्रतिशत में प्रतिश्वक राणि परन्तु यह तब तक कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी प्रन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बाबत संदत्त रक्षम की कुल धनराणि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रूपए तथा संख्थानों के मामले में 25,000 रूपये से प्रधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रक्षम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता मंस्था को जो किसी रूप में बैंक का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी।
- (2) उक्त बैंक ब्रारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संवाय प्रादेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसकी प्रिधि-स्थान प्रवृत्त होता है, ग्रसंदत्त रह जाती है;
- (3) तारीख 19 ग्रगस्त, 1989 को या उसमे पूर्व संप्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात वसूल किए गए बिलों की रकम;
- (4) कोई ऐसा ख्यंय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरूद्ध फाइल किए गए किसी वाद या प्रपील के संबंध में या बैंक द्वारा प्रभिप्राप्त डिकी के संबंध में या उसको देय किसी रक्षम को वसूल करने के लिए ग्रावण्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या प्रपील या डिकी या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रुपये से ग्राधक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित प्रनुजा इसके उपगत किए जाने से पूर्व ग्राधिप्राप्त की जाएगी; और
- (5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कम्पनी के प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिये बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छः कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मददे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अविध के दौरान उस मद के मददे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में मद पर व्यय 2,500 रूपये

- से स्रिधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित स्रनुज्ञा स्रितिरक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिन्नाप्ति की जाएगी।
- (ख) तारीख 19 ग्रगस्त, 1989 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के ग्रनुमरण के सिवाए श्रपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय अंतर या उसका ग्रन्थथा व्ययन नहीं करेगा।
- 3. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि बैंक प्राफ थंजावूर लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालाविध के दौरान निम्नलिखित और संदाय प्रश्रांत बैंक ऑफ यंजावूर लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुपंगी या किसी प्रन्य बैंक द्वारा बैंक ग्राफ थंजावूर लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों या ग्रन्थ प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों/ग्रिग्रियों के या दिए गए प्रतिदार के लिए ग्रावश्यक है, और जो उस तारीख को जिसको ग्रिधस्थगन ग्रावेश प्रवृत्त होता है, ग्रसंदत्त है ग्रितिरक्त संदाय कर सकता है।
- 4. केन्द्रीय सरकार, यह और निवेश देती है कि प्रधि-स्थान की कालावधि के दौरान बैंक ग्राफ थंजावूर लिमिटेड पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किसी श्रन्य बैंक के पास श्रपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगी, परन्तु इस ग्रादेश की किसी बात का यह ग्रयं नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी श्रन्य पूर्वोंक्त बैंक से श्रपना यह समाधान करने की ग्रपेक्षा करती है कि इस ग्रादेश द्वारा श्रधिरोपित शर्तों का यंजावूर बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।
- 5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेण देती है कि बैंक आफ थंजायूर लिमिटेड अधिस्थान की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को, जिनकी बसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गण अनुरोध पर उस दिशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं हैं।
- 6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि बैंक आफ यंजावूर लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्न-लिखित रीति में और विस्तार तक निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवर कु फ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है, भ्राडमानित, विलंगमित या बंधक या श्रस्यथा प्रभारित किया गया है: ~
  - (1) किसी ऐसी दशा में जिसमें, यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के मब्बे पूर्व संदाय बैफ द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और

(2) किसां अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, नीच उक्त माल या प्रतिभृतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मान्ना तक जो मायथ्यक या सम्भव हो।

[सं·. 17/5/89-बी ओ. III]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th August, 1989

- S.O. 652 (E) .—In exercise of the powers confered by sub-section (2) of section 45 of the Banking legulation Act, 1949, (10 of 1949) the Central lovernment, after considering an application made y the Reserve Bank of India under sub-section (1) f that section, hereby makes an order of Moratoim in respect of the Bank of THANJAVUR LTD. or the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th Decemer, 1989 and hereby stays the commencement or ontinuance of all actions and proceedings against hat banking company during the period of moratoium, subject to the condition that such stay shall not n any manner prejudice the exercise by the Central Sovernment of its powers under clause (b) of subection (4) of section 35 of the said Act or the exerise by the Reserve Bank of India of its powers inder section 38 of the said Act.
- 2. The Central Government hereby also directs hat during the period of meratorium granted to it, he Bank of THANJAVUR LTD. shall not, without he permission in writing of the Reserve Bank of ndia,
  - (a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder:
    - (i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000 and in the case of institutions Rs. 25,000 and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way:

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and ramaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) the amounts of the bills received or collection on or before the 19th August 1989 and realised before, on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the Said Bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding in excess of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and
- (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-today administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional ex penditure is incurred;
- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.
- 3. The Central Government hereby also directs that the Bank of THANJAVUR LTD, may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the Bank of THANJAVUR LTD., by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining un paid on the date on which the order of moratorium comes into force.
- 4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Bank of THANJAVUR LTD., shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Bank of THANJAVUR LTD.

- 5. The Central Government hereby further directs that the Bank of THANJAVUR LTD., may, during the period of maratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has o right to title o, or iterest in, such bills.
- 6. The Central Government hereby also directs that the Bank of THANJAVUR LTD., may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or over draft
  - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as , the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and
  - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17]5|89-BO-III]

का .आ. 653 (अ).--केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनिय-मन् अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) हारा प्रवत्तः शक्तियों का मयोग करते हुए, **उस.धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक** बाराः तिष्का गए अस्त्रेदन पर विचार करने तास्चात् पारुर सेंन्ट्रल बैंक लिमिटेड की बाबत 19 अगस्त, 1989 की कारबार की समाप्ति से धारीख 19 सितम्बर, 1989 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिए आधिस्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की काला-वधि के दौरान उस बैंककारी क्रक्यनी के विरुद्ध कार्रवाइयों और कार्यवाइयों के प्रारम्भ करने या चान् शर्त के अधीन रहते हुए स्थमित करती रखने की इस है कि ऐसे स्थान से उन्त अधिनियम की धारा 35 (4) मे खण्ड (ख) के अजीन केन्द्रीय की उपधारा प्रारकार : द्वारा । इसकी ः एक्तियों के प्रयोगः पर या उक्त 38 के अधीन भारतीय दिलवें बैंक अधिनियम की धारा द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं प्रद्रेगा ।

- 2. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश वेती है कि पासर सैन्द्रल बैंक लिमिटेड को मंजूर की गयी आधिस्थणन की कालावधि के दौरान, यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की जिल्लिस अनुता के बिना--
  - (क) अपने बाबिरकों और बाइयताओं के निर्वहन में या अव्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें उसके

- पश्चात उपबंधिय विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझीता या इंहराब नहीं करेगा।
- (1) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में बाहे वह किसी भी नाम से जात हों, कुल अतिशेष के 50 प्रतिश्वास से अनिश्वक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयेक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बाबत संबंध रक्त की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपये तथा संस्थाओं के मामले में 25,000 रुपए से अधिक नहीं है, परन्त यह और कि ऐसी कोई रक्तम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता संस्था की जो किसी रूप में बैंक का ऋणी है, संबंध नहीं की जाएगी
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए केई ब्राफ्टः या, संदाय आदेशों की कोई रक्त और जो उस समरीख को जिसका अधि-स्थान प्रवृत्त होता है, असंदत रह व्याती है;
- (3) बादी खं 19 अगस्त, 1989 को या उसमे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस बारी खं के पूर्व को या उसके पाचात वसूल किए गए खिलों की ∤रकम;
- उक्त वैक बारा या (4) कोई ऐसा व्यय ।सके अधिकड काइल किए गय किमी ाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा गभिप्राप्त डिकी के संबंध में या उसकी ्किमी रकम को बसूल करने के आवार्यक ः रूप से उपगत्त किया जाना है, परन्त यदि ऐसे प्रत्येक बाद या या डिकी या कार्यवाही बाबत म्पय 2,500 हप ये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित अनुता इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की अभएगी; और
- (5) किसी: अन्य पद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह वह विकासरी कम्पनी ह के प्रतिविन के अधासन का संजालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, प्रस्तुः जहां किसी पद पर कृत वस अधिस्था न के आदेश के पूर्व मालके दौरान उन मद के मद्दे कले डर औसत मागिक 7**7**7 अधिक पा जहां अवधि के दौरान उन , **3**4त मद के महे कोई क्यम उपगत नहीं हुआ

है और ऐसे में मद पर व्यय 2500 हपये से अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुजा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिश्राप्ति की जाएगी।

- (ख) तारी ख 19 अगस्त, 1989 को कारबार की समान्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए अपनी स्थावर सम्पत्ति का विकथ अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।
- केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पारूप **बैक लिमिटे**ङ उसे मंजूर की गई स्थगन को सैम्टल कालावधि के दौरान निम्नलिवित और संदाय, अर्थात पारूर सैन्ट्रल लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुषंगीयाकिसी अन्य बैंक द्वारा पारूर सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड को सरकारी फ्रिसिमितियों के विरुद्ध ं उधारों/अग्निमों के या दिए गए प्रसिवास के लिए आवस्यक है और जो उस तारीख को आदेश प्रवृत्त होता है, असंदत्त अधिस्थगन जिसको है अतिरिक्त संदाय कर सकता है।
  - 4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश वेती है कि अधिस्थान की कालावधि के दौरान पारुर सैन्ट्रन बैंक किमिटेड पूर्वीक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुशात होगी, परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भार-गिय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना महसम्मधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित मातों का पारूर सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड के क्या में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।
  - 5. केन्सीय सरकार यह और निवेण देती है कि पारूर सन्दूल बैंक लिमटिस अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, एसे किन्हीं बिलों को, जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसकी प्राप्त करने के लिए इक्टार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस विशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।
  - 6. भेन्द्रोय सरकार यह भी निदेश दती है कि पारूर सैन्द्रल बैंक । लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभृतियों को निम्न-लिखित रीति में और विस्तार तक निमुक्त या परिवक्त कर सकेगा जो किसी उधार मकद प्रत्यय यो औवर-कृपक्ट के लिए इसके पास गिरवी रहा गया है

आडमानित, विलंगमित या बंधक या अन्यया प्रमारित किया गथा है:---

- (1) किसी ऐसी दशा में जिसमें, ययास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के मुद्दे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और
- (2) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जा अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखें गये थे, इन दोनों में जा भी उच्चतर हो, नोचे उकत माल या प्रतिभृतियो पर सोमाओं के अनुपात का कम किए जिना ऐसी माला तम जा आवश्यक या संभव ही.

[सं. 17/7/89-वी ओ-III(i)

- S.O. 653(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the PARUR CENTRAL BANK LTD, for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.
- 2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the PARUR CENTRAL BANK LTD., shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—
  - (a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder.
    - (i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000|- and in the case of institutions Rs. 25,000 and provided further that no amount hall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 19th August 1989 and realised before, on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500|- the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and
- (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500[-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;
- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.
- 3. The Central Government hereby also directs that the PARUR CENTRAL BANK LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the PARUR CENTRAL BANK LTD. by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.
- 4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the PARUR CENTRAL BANK LTD. shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the PARUR CENTRAL BANK LTD.

- 5. The Central Government hereby further directs that the PARUR CENTRAL BANK LTD. may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.
- 6. The Central Government hereby also directs that the PARUR CENTRAL BANK LTD., may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit overdraft
  - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and
  - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17|89-80-III(i)]

## अधिपुचना

का. आ. 654 (अ).--केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनि-अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) बारा प्रदत्त शक्तियों का हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भार-रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर् पूर्वावल बैंक लिभिटेड पश्चात 19 अगस्त, को कारबार की समाध्य जिनके अलर्गत 1989 त्रक कालावधि अधिस्यगन भी हैं, निय और अधिस्यगत आदेश करती कालावधि के दौरान उस बैककारी कम्पर्नः और कार्यवाईयों के प्रारम् न सभी कार्यवाहियों को इस शर्त के अधीन चाल रखने से उ≉त स्थगित करती है कि ऐसे स्थमन की धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उसकी मित्रियों के द्वारा केन्द्रीय सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीत भारतीय रिजर्भ शक्तियों के प्रयोग पर प्र∄ाह्र्य उसकी द्वारा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- 2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पूर्वाचल वैंक लिमिटेड को मंजूर की गया अबिस्थान का काला-विधि के दौरान, यह बैंक मारतीय रिर्जा बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना —
  - (क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं से निवंहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा,

कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिये करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगाः—

- (1) प्रत्येक बचत वैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निश्नेप में चाहे वह किसी भी नाम से जात हो, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत से अनिधि राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के माथ संयुक्त रूप नहीं) जमा खाते की बाबत संदत्त रकम की कुल धनराणि में 10,000 रुपये व्यक्तियों के मामले तथा संस्थाओं के मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्त यह ऐसी कोई रकम ऐ से और कि किसी निक्षेपकर्ता संस्था को जो किसी में बैंक काऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी:
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफट या संवाय की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंदत्त रह जाती है;
- (3) तारीख 19 अगस्त, 1989 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिये प्राप्त और उस तारीख से पूर्व को या उसके पश्चात बसूल किए गए बिलों की रकम;
- (4) कोई ऐसा व्यय जो बैंक हारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी बाद अपीध के संबंध में उक्त वैक द्वारा अभिप्राप्त ভিকী के संबंध में या उसको देथ किसी रकम वसूल करने के लिए **आवश्य**क उपगत किया जाना परन्त् यदि ऐसे प्रत्येक याद या अपील या डिकी या कार्यवाही की बाबत व्यय 2:500 सपये से अधिक है तो भार तीय रिजर्व वैक की लिखित अनज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी;
- (5) किसी अन्य मव पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारो के प्रतिवित के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु अहां किसी मव

- पर कुल व्यय, अधिस्थान के आदेश पूर्व ন্ত: केलेंडर माय दौरान उस मद के महे औसत मासिक व्ययसे अधिक है या जहां उक्त अवधि के दौरान उसामद के महें कोई अन्य उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में मद पर व्यय 2,500 रुपये से अधिक भारतीय वहां रिजर्व बैक लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त भ्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्तकी जाएगी।
- (ख) तारीख 19 अगस्त, 1989 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।
- 3. केन्द्रीय सरकार सरकार यह भी निदेश देती है कि पूर्वीचल बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थान की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संवाय, अर्थात् पूर्वाचल बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या अर्थात् पूर्वाचल बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या असके किसी समनुषगी या किसी अन्य बैंक द्वारा पूर्वाचल बैंक लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों/अग्निमों के या विए गए प्रतिदाय के लिये आवश्यक है और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थान आवेण प्रवृत्त होता है, असंदत्त है अतिरिक्त संवाय कर सकता है।
- 4. फेन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देशी है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान पूर्वाचल लिमिटेड पूर्वांक्त संवाय करने के प्रयोजन के लिये भारतीय रिजावं बैंक किसीअन्य बैंक के पास अपना खाता , चलाने केलिये अनुज्ञात होगो परन्त् इस आदेश किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरीपित शर्ली का पूर्वीवल बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रक्षम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।
- 5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हक्तदार ध्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दिशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं हैं।

- 6. केन्द्रीय मरकार यह भी निदेश देती है कि पूर्वी-चल बैंश निसिटेड ऐसे माल या प्रतिभित्तियों को निम्मानिवित रीति में और वितार तक निर्मुक्त या परिदक्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवरष्ट्राफट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है ब्राइमानित, विलग मित या बंधक या श्रन्यथा प्रभारित किया गया है:—
  - (1) किसी ऐसी दशा में यथास्थिति. जिसमें उद्यार लेने वालों सेने वाले उधार रकमों के महे पूर्ण संदाय मे सभो बैंक द्वारा बिना मर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और
  - (2) किसी प्रत्य दशा में प्रनुशंधित ध्रनुपातों या ऐसे ग्रनुपातों से जो ग्रिधिस्थगन ग्रादेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो नीचे उक्त माल या प्रतिभृतियों पर सीमाओं के ध्रनुपात को कम किए बिना ऐसी मान्ना तक जो ग्रावश्यक या संभव हो ।

[स. 17 /7/89 बी ओ. III (ii)]

- S.O. 654(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949) the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the PURBANCHAL BANK LTD. for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratosubject to the conditions that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.
- 2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the PURBANCHAL BANK LTD, shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India.—
  - (a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder:
    - (i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the

- name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000 and in the case of institutions Rs. 25,000 and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;
- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force:
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 19th August, 1989 and realised before, on or after that date:
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and
- (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500 the permission in writing the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;
- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.
- 3. The Central Government hereby also directs that the PURBANCHAL BANK LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the PURBANCHAL BANK LTD. by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.
- 4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the PURBAN-CHAL BANK LTD, shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with

any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the PURBANCHAL BANK LTD.

- 5. The Central Government hereby further directs that the PURBANCHAL BANK LTD. may during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persions, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.
- 6. The Central Government hereby also directs that the PURBANCHAL BANK LTD, may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft:—
  - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Bank, unconditionally; and
  - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17|7|89-80-JII(ii)]

का. आ. 655(अ).--केन्द्रीय सरकार वैककारी ग्रधिनियम 1949 (1649 का 10) की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का धारा 45 की उप धारा (2) धारा की उपधारा (1) करते ŝú. उस भारतीय रिजर्व वैंक द्वारा किए भावेदन पर विचार करने के पश्चात बैंक भ्राफ तमिलनाडु 19 अन्नरस 1989 को कारबार की लिमिटेश की बाबत 19 दिसम्बर 1989 तक जिसके से तारीख श्रन्तर्गत यह तारीख भी है की कालावधि के लिये अधि-स्यगत ब्रादेश करती है और ब्रधिस्यगन को कालाबधि के दौरान उस बैककारी कम्पनीके विरुद्ध सभी कार्यवाईयों और कार्यवाईयों के प्रारम्भ करने या चालू रखने की इस गर्त के भ्रवीन रहते हुए स्थगित करती एसे स्थवन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा के खण्ड (ख) के श्रधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी मक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- 2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि बैंक ब्राफ तमिलनाडु लिमिटेड को मंजूर की गयी ग्रिधिस्थमन की कालावधि के दौरान वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुका के बिना ——
- (क) ग्रपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में या श्रन्यथा कोई उठार या श्रप्रिम नहीं 2318 GI/89—2

देगा, कोई दासित्य उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिए करार या उसका मंवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पण्चात् उपवंधित विस्तार और रोति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :—

- (।) प्रत्येक बचत बैंक या चाल स्वानं किसी अन्य निशेष में नाहे वह किसी भी नाम से जात हो, कुल अतिशेष के 50 प्रति-शत से अनिधिक राणि परन्तू यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बचत की कल संदत्त रकम धनराणि व्यक्तियों के मामले मे रुपये तथा मस्थाओं के मामले में 25,000 रुपये स अधिक नहीं ₹, परन्तू यह ऐसी और कि कोई ऐसे किसी रकम में बीक∜ निक्षेपकर्ता संस्था को जो किसी 延年 का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी।
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संदाय आदेणों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिस को अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंदत्त रह जाती हैं;
- (3) तारीख 19 अगस्त, 1989 को या उससे पूर्व सग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात् वसूल किए गए बिलों की रकम ;
- (4) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाईल किए गए किसी बाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिकी संबंध के देय किसी या उसको रकम वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तू यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील डिक्री या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 ₹. अधिक तो रिजर्व बैक की लिखित अनजा इसके किए उपगत जाने से पुर्व अधिप्राप्त जाएगी; और
- (5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य ब्यय जहां तक बैंक-कारी कम्पनी के प्रति दिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी मद पर कूल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के कैलेंडर मास के दौरान ओसत मासिक रुपय से अधिक है जहां उक्त अवधि के दौरान उस मद के मद्दे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और में मद ऐसे पर व्यय 2500 रुपये से

अधिक हैं वहा भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त क्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी।

- (ख्र) ताराख 19 अगस्त, 1989 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए अवनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।
- 3. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती हैं कि बैंक आफ तिमलनाडु लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थान की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय, अर्थात्:— बैंक आफ तिमलनाडु लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुषंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा बैंक आफ तिमलनाडु लिमिटेड को सरकारी प्रतिभृतियों या अन्य प्रतिभृतियों के विरुद्ध उधारों/अग्निमों के या दिए गए प्रतिदाय के निए आवण्यक है, और जो उस तारीख को जिमकी अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असेंदत्त है, अतिरिक्त संदाय कर मकता है।
- 4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देती है कि अधिस्थान की काल(वधि के दौरान बैंक आफ तिमलनाडु लिमिटेड पूर्वीक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बेंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुशात होगी, परन्तु इस आदेश की किसी यात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएना कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वीक्त बैंक मे अपना यह ममाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित जातीं का बैंक आफ निलनाडु निमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।
- 5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि बैंक आफ तिमलनाडु लिमिटेड अधिस्थीन की कालाविध के दौरान ऐसे किन्हीं बिलों को जिनकी वसूली नही हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दिशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे विलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।
- 6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि वैके आफ तिमलनाडु लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूमियों को निम्न-लिखित रोति में और विस्तार तक नर्मुक्त या परिदक्त कर सकेगा जो किसी उधार नकद प्रत्यय या ओवर ट्राफट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है, आडमानित विसंगमित या बंधक या अन्यथा प्रभारित किया गया है:——
  - (1) किसी ऐंसी द्रशा में जिसमें यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों में देय सभी रकमों के महे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा

बिना मर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और

(2) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होते से पूर्व रखेगए थेइन दोनों में के जो उच्चसर हो, नीचे उक्त भाख प्रतिभृतियां पर सीमाओ के अनुपात की कम किए किए विना एसी मावा सक जो आवश्यक या संभव हो

> [सं. 17/7/89-बीआ III (iii)] मंन्त्रेवर झा, संयुक्त सचिव

- S.O. 655 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949) the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under Sub-Section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the Bank of TAMILNAD LTD., for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of subsection (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its nowers under section 38 of the said Act.
- 2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the Bank of TAMILNAD LTD., shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—
  - (a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder:
    - (i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000|- and in the case of institutions Rs. 25,000|- and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;
    - (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining

- unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 19th August, 1989 and realised before, on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceedings is in excess of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and
- (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that is on during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that past exceeds a sum of item in the Rs. 2500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;
- (b) Sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.
- 3. The Central Government hereby also directs that the Bank of TAMILNAD LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities, to

- the Bank of TAMILNAD LTD. by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.
- 4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Bank of TAMILNADU LTD., shall be permitted to tperate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Bank of TAMILNAD LTD.
- 5. The Central Government hereby further directs the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.
- 6. The Central Government hereby also directs that the Bank of TAMILNAD LTD., may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft
  - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and
  - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17|7|89-BO-III(iii)] MANTRESHWAR JHA, Jt. Secy.